3. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कार्य
(ROLE OF MONEY IN A CAPITALIST ECONOMY)

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता उत्पादक तथा संसाधनों के स्वामी के रूप में पर्याप्त आर्थिक स्वतंत्रता के साथ आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है। व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं को निजी सम्पत्ति की संस्था, लाभों का उद्देश्य, उद्यम की स्वतंत्रता और उपभोक्ता प्रभुत्व नियंत्रित करते हैं। सभी उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और उनका प्रबंध ऐसे व्यक्ति करते हैं जिन्हें प्रवर्त्तमान कानूनों के अनुसार उत्पादन के साधनों को ठिकाने लगाने की स्वतंत्रता होती है। व्यक्तियों को यह छूट होती है कि वे चाहे जो व्यवसाय चुनें और चाहे जितनी वस्तुएं तथा सेवाएं खरीदें और बेचें।

इस तरह की अर्थव्यवस्था निश्चय ही मुद्रा-अर्थव्यवस्था होती है जहां अर्थव्यवस्था के संचालन में मुद्रा महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों को आय की प्राप्ति मुद्रा में होती है। उपभोक्ताओं के पास श्रम, भूमि और पूंजी-ये उत्पादन के साधन होते हैं—इनकी सेवाएं बेचने से उन्हें मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभांशों के रूप में मुद्रा आय प्राप्त होती है। वे अपनी मुद्रा आय को उन वस्तुओं तथा सेवाओं पर खर्च कर सकते हैं, जिन्हें भी वे खरीदना चाहते हैं। वे चाहें तो अपनी मुद्रा का कुछ भाग खर्च करें और कुछ बचा लें।

फिर, बड़ी और छोटी फर्में वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की सेवाएं खरीदती हैं। ये सेवाएं मुद्रा के हिसाब से ख़रीदी जाती हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ का उद्देश्य ही समस्त उत्पादन प्रक्रिया को निर्धारित करता है। परिव्यय और प्राप्तियों का अन्तर ही लाभ होता है। इन सबका लाभ, परिव्यय और प्राप्ति का हिसाब मुद्रा में लगाया जाता है।

वास्तव में, इस तरह की अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह चक्रीय होता है। सभी फर्में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के साधनों की सेवाओं की मांग करती हैं। सभी उत्पादन के साधनों की सेवाओं का भुगतान मुद्रा में किया जाता है और इस मुद्रा से उपभोक्ता वस्तुएं खरीदी जाती हैं। इस प्रकार मुद्रा वापस फर्मों के पास आ जाती है और फर्में पुनः विविध प्रकार की वस्तुओं को और उत्पादन में उपभोक्ता की सेवाओं के बदले उन्हें मुद्रा में भुगतान करती हैं।

(1) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा और कीमत तंत्र (Money and the Price mechanism in a capitalist Economy)—मुद्रा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य कीमत तंत्र के चालन में करती है। कीमत प्रणाली वस्तुओं तथा सेवाओं के माध्यम से कार्य करती है। कीमतें अनगिनत वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन को निर्धारित करती हैं। कीमतें उत्पादन का संगठन करती हैं और वस्तुओं तथा सेवाओं के

Scanned with CamScanner

वितरण में सहायक होती हैं। क्योंकि कीमतें मुद्रा में व्यक्त की जाती हैं इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के बिना कीमत तंत्र नहीं चल सकता।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और उत्पादन भी निजी उद्यम करते हैं, इसलिए इस तरह की अर्थव्यवस्था में मुद्रा केन्द्रीय समस्याएं हल करने का महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। यह कार्य कीमत-तंत्र के माध्यम से होता है। कीमत-तंत्र सरकार के किसी निर्देश व नियंत्रण के बिना अपने आप चलता है।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की केन्द्रीय समस्याएं—जैसे क्या, कितना, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए—कीमत तंत्र के माध्यम से सुलझाई जाती हैं। इन पर आगे विचार किया जा रहा है।

क्या, कितना और कैसे उत्पादन किया जाए? इस समस्या को लाभ के उद्देश्य के आधार पर कीमत तंत्र सुलझाता है। किसी फर्म के खर्च और आमदनी का अन्तर लाभ होता है। लाभ की मात्रा वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करती है। कीमतों और लागतों में जितना ही अधिक अन्तर होगा, लाभ भी उतना ही अधिक होगा। फिर, कीमतें जितनी ही अधिक होंगी, उत्पादक विभिन्न मात्राओं मे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने का उतनी ही अधिक प्रयत्न करेंगे। दूसरी ओर, कीमतें उपभोक्ताओं के विविध वस्तुओं के चुनावों पर निर्भर करती हैं। उपभोक्ताओं के चुनाव भी यह निर्धारित करते हैं कि किस चीज का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, किस प्रकार उत्पादन किया जाए और किस तरह उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन किया जाए।

वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं और उत्पादकों के बीच जो प्रतियोगिता रहती है वह वस्तुओं और सेवाओं की मांग तथा पूर्ति को बराबर करती है। क्योंकि पूंजीवाद के अन्तर्गत काफी लचीलापन रहता है, इसलिए कीमतें अपने आपको मांग में, उत्पादन की तकनीकों में, उत्पादन के साधनों की पूर्ति में, होने वाले परिवर्तनों के साथ समायोजित करती रहती हैं। कीमतों में जो परिवर्तन होते हैं, वे आगे उत्पादन के साधनों की मांग तथा उपभोक्ता आय में समायोजन स्थापित करते हैं। इसलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत कीमत-तंत्र का आधार मुद्रा है। यह ऐसी धुरी है जिसके गिर्द समस्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था घूमती है। क्योंकि इस तरह की अर्थव्यवस्था बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के चलती है, इसलिए उपभोक्ताओं की जरूरतों और उत्पादकों के लाभ को अधिकतम बनाने में मुद्रा बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य करती है।

2. उपभोक्ता के लिए (For the Consumer)—पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उपभोक्ता ही बादशाह होता है, जो दी हुई मुद्रा आय से केवल वही वस्तएं खरीदता है जो उसे अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती हैं। ऐसा वह उन विभिन्न वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताओं को बराबर करके करता है जिन्हें वह खरीदना चाहता है। जब प्रत्येक वस्तु की मुद्रा में व्यक्त कीमत उसकी सीमान्त उपयोगिता के बराबर हो जाती है तो, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार मुद्रा की सहायता से उपभोक्ता उन विविध वस्तुओं में से तर्कसंगत चुनाव कर सकता है जिन्हें वह अपनी दी हुई मुद्रा आय से खरीदना चाहता है।

चित्र 2.1 इस तर्क की व्याख्या करता है। मानलीजिए कि केवल दो वस्तुएं ही उत्पादित की जाती हैं। वे पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं हैं जो क्रमशः अनुलंब और क्षैतिज अक्ष पर ली गई हैं। उत्पादन संभावना वक्र PP_1 उपभोक्ता का चुनाव क्षेत्र व्यक्त करता है। यह उत्पादक पर निर्भर करता है कि वह विवेकपूर्ण चुनाव पर निर्भर करते हुए पूंजीगत वस्तुएं अथवा उपभोक्ता वस्तुएं उत्पादित करे।

Scanned with CamScanner

उपभोक्ता B तथा C संयोग में से चुनेगा जो उसे दी हुई आय से अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। PP_1 वक्र के किसी भी बिन्दु की तुलना में उपभोक्ता संयोग A पर दोनों वस्तुओं की कम मात्राएं खरीदेगा और संतुष्टि के निचले स्तर पर होगा।

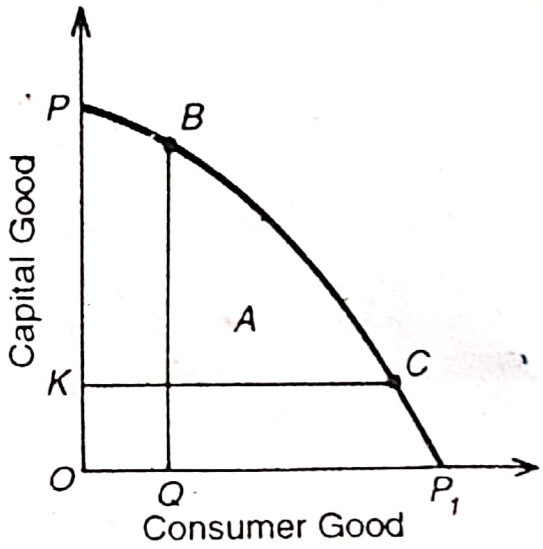

चित्र 2.1

3. उत्पादक के लिए (For the Producer)– मुद्रा, उत्पादक के लिए भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जितनी उपभोक्ता के लिए। उत्पादक, आगतों को मुद्रा में खरीदता है और निर्गतों को मुद्रा में बेचता है। क्योंकि उसका लक्ष्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, इसलिए वह सीमान्त लागत और सीमान्त आय का हिसाब मुद्रा में लगाता है। लाभ तब होता है जब सीमान्त आय अधिक हो और इन लाभों से आगे उत्पादन बढ़ता है। जब सीमान्त आय से सीमान्त लागत बढ़ जाती है तो हानि होती है और उत्पादन घट जाता है। परन्तु ये स्थितियां बहुत देर तक नहीं चलतीं। कीमत- तंत्र सीमान्त आय और सीमान्त लागत में ऐसी कीमतों पर संतुलन स्थापित कर देता है जिन्हें फिर समायोजन की जरूरत नहीं रह जाती। इस प्रकार उत्पादकों को सामान्य लाभ प्राप्त होता है जिसे वे मुद्रा के रूप में पाते हैं।

4. पूंजीवादी उत्पादन का आधार (Basis of Capitalistic Production)—वास्तव में पूंजीवादी उत्पादन का आधार ही मुद्रा है। आगतों की खरीद को सुविधाजनक बनाकर और विशिष्टीकरण एवं श्रम के विभाजन को बढ़ाकर मुद्रा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कृषि, उद्योग और तृतीयक क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने में सहायक होती है। क्योंकि ये सभी क्षेत्र परस्पर निर्भर हैं और मुद्रा के माध्यम से परस्पर विनिमय पर आधारित हैं, इसलिए पूंजीवादी उत्पादन बढ़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों से वस्तुओं तथा सेवाओं के चक्रीय प्रवाह के माध्यम से मुद्रा, पूंजीवादी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होती है।

5. साख का आधार (Basis of Credit)—उत्पादन की समस्त पूंजीवादी प्रणाली साख पर आधारित है। साख के साधन मुद्रा का ही रूप हैं जिन्हें बैंक इसलिए जारी करते हैं कि पूंजीवाद के अन्तर्गत व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि को सुगम बनाया जा सके। साख साधनों के आधार पर ही बैंक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कर्ज देते हैं। साख के परिमाण को ब्याज की दर निर्धारित करती है जो ऋण-योग्य निधियों की कीमत को व्यक्त करती है और ऋणों को मुद्रा में व्यक्त किया जाता है।

6. पूंजी निर्माण का साधन (Means of Capital Formation)—पूंजीवाद का आधार ही पूंजी है और मुद्रा पूंजी का सबसे अधिक तरल रूप है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि पूंजी संचय पर निर्भर करती है और पूंजी संचय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी मुद्रा आय को बचाते हैं और बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं में जमा करते हैं; जो उन्हें आगे पूंजी परिसम्पत्तियों में निवेश के लिए कृषकों, उद्योगपतियों, परिवाहकों तथा अन्य व्यापारियों को उधार देती हैं। पूंजीवाद के अन्तर्गत पूंजी निर्माण की प्रक्रिया की जितनी भी अलग-अलग अवस्थाएं हैं, जैसे आय प्राप्त करना, बचत करना और निवेश

Scanned with CamScanner

करना, वे सभी मुद्रा के रूप में ही की जाती हैं।

7. वर्तमान और भविष्य में संबंध स्थापन (Link between the Present and Future)—पूंजीवाद के अन्तर्गत उद्यम की स्वतंत्रता तथा उपभोग की स्वतंत्रता के माध्यम से मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच संबंध स्थापित करती है। उपभोक्ता के लिए उपभोग की स्वतंत्रता से उपभोक्ता को अपनी आय का कुछ भाग बचाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बचतों के परिणामस्वरूप वे निवेश के माध्यम से पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन होता है और पूंजीगत वस्तुएं अर्थव्यवस्था की वृद्धि में योगदान देती हैं। इसी प्रकार पूंजीवाद के अन्तर्गत उद्यम की स्वतंत्रता दुकानदारों और व्यापारियों को सुविधा प्रदान करती है कि वे वर्तमान में किये गए सौदों का भुगतान भविष्य में कर दें। यह मुद्रा के माध्यम से ही संभव हो पाता है जब वस्तुओं का संग्रह वर्तमान में किया जाता है और उन्हें बेचा भविष्य में जाता है। इन तरीकों से मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच संबंध स्थापित करती है।

8. व्यापार चक्रों के लिए उत्तरदायी (Leads to Business Cycles)—पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की इन प्रत्यक्ष खूबियों के अलावा, उसका एक गम्भीर दोष यह है कि मुद्रा के बहुत बढ़ जाने से स्फीति और मुद्रा की कमी से अवस्फीति आती है। मुद्रा की मात्रा में होने वाले इन परिवर्तनों का परिणाम यह होता है कि अर्थव्यवस्था पर चक्रीय उतार-चढ़ाव और उनके सम्बद्ध प्रभाव पड़ते हैं। वास्तव में, जब मुद्रा की पूर्ति बहुत बढ़ती है तो वह अधिक मांग उत्पन्न करती है, जिससे आगे अति-उत्पादन होता है और बाजार में वस्तुओं की भरमार हो जाती है और अन्ततः मंदी आती है और भारी बेरोजगारी फैल जाती है। इस प्रकार जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र चलते हैं तो संसाधन बेकार जाते हैं और उत्पादन में हानि होती है। परन्तु शूम्पीटर मानता है कि व्यापार चक्र तो आर्थिक विकास की कीमत है, जो चुकानी पड़ेगी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गतिशील मार्ग की स्थायी विशिष्टता है और हर बार जब भी व्यापार चक्र आता है, वह विशिष्टता अर्थव्यवस्था को विकास के अगले ऊंचे स्तर पर ले जाती है।

सारांश यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के परिचालन में मुद्रा बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य करती है।

4. समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका (MONEY IN A SOCIALIST ECONOMY)

समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और वितरण पर केन्द्रीय प्राधिकरण का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। सभी खानों, फार्मों, कारखानों, वित्तीय संस्थाओं, वितरक एजेन्सियों (जैसे आन्तरिक और बाह्य व्यापार, दुकानें, भंडार आदि) परिवहन और संचार के साधनों आदि का स्वामित्व, नियंत्रण तथा नियमन सरकारी विभागों और राज्य निगमों के हाथ में होता है। इसलिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण की प्रक्रिया स्वतंत्रता से नहीं चलती अपितु केन्द्रीय योजना प्राधिकरण के नियंत्रण तथा नियमन के अन्तर्गत कार्य करती है।

1. समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा और कीमत तंत्र (Money and Price Mechanism in a Socialist Economy)—समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र की कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि इसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था समझा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के विविध तत्त्व, अर्थात् लागतें, लाभ और कीमतें, योजनाबद्ध होते हैं और योजना के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों के अनुसार योजना प्राधिकरण उनका हिसाब लगाता है। इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का तर्कसंगत आर्थिक आकलन अथवा आवंटन संभव नहीं है। आइए, हम देखें कि समाजवादी-समाज

Scanned with CamScanner

अर्थव्यवस्था की केन्द्रीय समस्याओं—क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए—कैसे हल करता है।

क्या उत्पादित किया जाए?—समाजवादी समाज में केन्द्रीय योजना प्राधिकरण ही बाजार के कार्य करता है। क्योंकि उत्पादन के सभी भौतिक साधनों पर सरकार का स्वामित्व, नियंत्रण और निर्देश होता है, इसलिए इस बात का निर्णय कि किस चीज का उत्पादन किया जाए, केन्द्रीय योजना के ढांचे के भीतर ही किया जाता है। उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति और उनकी मात्रा के संबंध में निर्णय इस बात पर निर्भर करते हैं कि केन्द्रीय योजना प्राधिकरण ने क्या उद्देश्य, लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। विविध वस्तुओं की कीमतें भी यही प्राधिकरण निर्धारित करता है। कीमतें निर्देशित (administered) होती हैं। वे सामान्य व्यक्ति के अधिमानों को प्रकट करती हैं। उपभोक्ता का चुनाव उन्हीं वस्तुओं तक ही सीमित रहता है जिनका उत्पादन और विक्रय करने का निर्णय योजनाकार करते हैं।

कैसे उत्पादन करना है?—इस समस्या का निर्णय भी केन्द्रीय योजना प्राधिकरण करता है। "यह उत्पादन के साधनों को मिलाने और प्लाण्ट के उत्पादन के पैमानों को चुनने के संबंध में, उद्योग का उत्पादन निर्धारित करने के संबंध में, संसाधनों के बटवारे के संबंध में और लेखाकरन में कीमतों के प्राचलिक (parametric) प्रयोग के संबंध में नियम बनाता है।" केन्द्रीय योजना प्राधिकरण प्लाण्ट-प्रबंधकों के मार्गदर्शन के लिए दो नियम निर्धारित करता है। एक तो यह कि प्रत्येक प्रबंधक उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे ढंग से मिलाए कि यदि हुए उत्पादन की औसत लागत न्यूनतम हो। दूसरे यह कि प्रत्येक प्रबंधक उत्पादन का वह पैमाना चुने जिससे सीमान्त लागत कीमत के बराबर हो जाए। क्योंकि अर्थव्यवस्था में सभी संसाधनों का स्वामित्व और नियमन सरकार का होता है, इसलिए कच्चा माल, मशीनें और अन्य लागत भी उन कीमतों पर बेचे जाते हैं जो उनके उत्पादन की सीमान्त लागत के बराबर हों। यदि किसी वस्तु की कीमत उसकी औसत लागत से अधिक होगी तो प्लाण्ट-प्रबंधक लाभ अर्जित करेंगे और यदि वस्तु की कीमत उसके उत्पादन की औसत लागत से कम होगी, तो उन्हें हानि उठानी होगी। पहली स्थिति में उद्योग का विस्तार होगा और दूसरी स्थिति में उद्योग को उत्पादन घटाना होगा। अन्ततः भूल और चूक (trial and error) प्रक्रिया से संतुलन की स्थिति आ जाएगी। पर, भूल और चूक की प्रक्रिया ऐतिहासिक रूप से दी हुई कीमतों के आधार पर चलेगी, इसलिए समय-समय पर कीमतों में छोटे-मोटे समायोजन करने जरूरी हो जाएंगे। इस प्रकार सार्वजनिक स्वामित्व में उत्पादन के और उत्पादन-संसाधनों के प्रबंधकों के सभी निर्णय तथा उपभोक्ताओं के रूप में तथा श्रम की पूर्ति करने वालों के रूप में व्यक्तियों के निर्णय इन कीमतों के आधार पर किए जाते हैं। इन निर्णयों के परिणामस्वरूप प्रत्येक वस्तु की मांग और पूर्ति की मात्रा निर्धारित होती है। यदि वस्तु की मांग की मात्रा वस्तु की पूर्ति की मात्रा के बराबर न हो, तो उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन करना पड़ता है। यदि पूर्ति मांग से बढ़ जाए तो कीमत बढ़ानी पड़ती है और पूर्ति से मांग कम हो तो कीमत घटानी पड़ती है। इस प्रकार केन्द्रीय योजना बोर्ड नई कीमतें नियत करता है जो नए निर्णयों का आधार बनती हैं और परिणाम यह होता है कि मांग और पूर्ति की नई मात्राएं निर्धारित होती हैं।

चित्र 2.2 में पूर्ति वक्र S एवं मांग वक्र D की सहायता से कीमत-तंत्र की प्रक्रिया की व्याख्या की जाती है। आरम्भिक अवधि में मान लो केन्द्रीय योजना बोर्ड वस्तु A की कीमत OP_1 निश्चित करता है। इतनी ऊंची कीमत पर उपभोक्ता केवल OQ_1 मात्रा खरीदने को तैयार हैं जबकि उत्पादन लक्ष्य

Scanned with CamScanner

OQ_1 पहले निर्धारित किया जा चुका है। प्रारम्भिक गणना अवधि की समाप्ति पर, उत्पादन प्रबंधक केन्द्रीय योजना बोर्ड को यह सूचित करेगा कि वस्तु A की Q_1Q_4 अतिरिक्त मात्रा स्टॉक में बची हुई है। द्वितीय अवधि में, केन्द्रीय योजना बोर्ड वस्तु की इस अतिरिक्त मात्रा को बेचने के लिए वस्तु की कीमत कम करने की नीति अपनाएगा, जिसके कारण वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। चित्र में जब वस्तु की कीमत OP_1 से कम होकर OP_2 हो जाती है तब उपभोक्ता वस्तु की OQ_4 मात्रा की मांग करते हैं। लेकिन OQ_2 मात्रा ही बेची जाती है। इसलिए प्रबन्ध उत्पादक बोर्ड को वस्तु की पूर्ति बढ़ाने का सुझाव देगा और साथ ही बोर्ड वस्तु की कीमत OP_2 से बढ़ाकर OP_3 कर देगा जहां वस्तु की मांग और पूर्ति OQ_3 के बराबर E बिन्दु पर हो जाएगी।

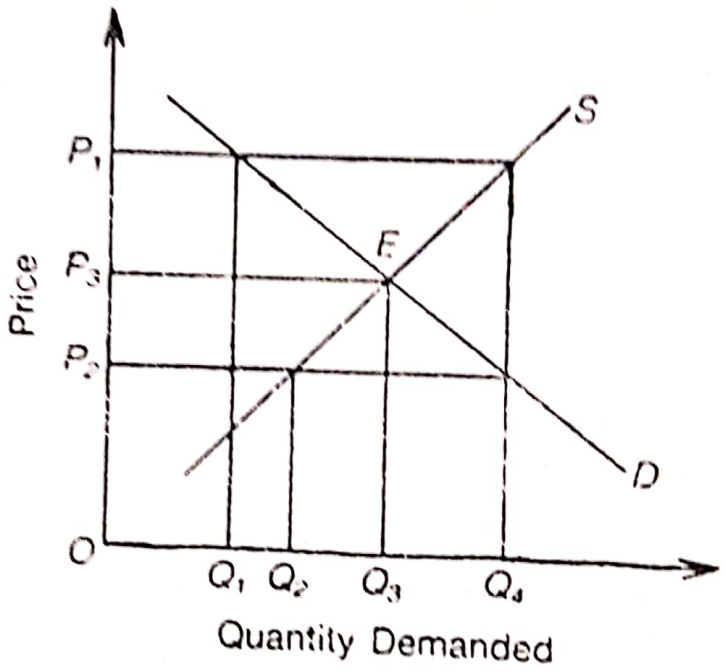

चित्र 2.2

किसके लिए उत्पादन किया जाए?—इस समस्या का समाधान समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य करता है। केन्द्रीय योजना प्राधिकरण इसके सम्बन्ध में उस समय निर्णय करता है जब वह योजना के समस्त उद्देश्यों के अनुसार यह निश्चित करता है कि क्या और कितना उत्पादन किया जाए। इसका निर्णय करने में सामाजिक अधिमानों को महत्त्व दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विलास की वस्तुओं की अपेक्षा उन वस्तुओं के उत्पादन को अधिक महत्त्व दिया जाता है जिनकी अधिकांश लोगों को जरूरत होती है। वे लोगों की न्यूनतम जरूरतों पर आधारित होती हैं और सरकारी भंडारों के माध्यम से नियत कीमतों पर बेची जाती हैं। क्योंकि मांग का पूर्वानुमान लगाकर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए जब मांग बढ़ती है, तो वस्तुओं की कमी हो जाती है और परिणामतः राशनिंग करना पड़ता है।

इस प्रकार समाजवादी समाज में आय-वितरण की समस्या अपने आप हल हो जाती है क्योंकि सभी संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है और उनका पुरस्कार भी नियत होता है जिसका भुगतान सरकार करती है। आर्थिक आधिक्य जानबूझकर उत्पन्न किये जाते हैं और पूंजी संचय तथा वृद्धि के लिए उपभोग में लाए जाते हैं। कीमतें निर्धारित करने का निर्णय इससे भी संबंधित होता है कि विभिन्न वस्तुएं कैसे उत्पादित की जाएं। इसके लिए केन्द्रीय प्राधिकरण संसाधनों का आवंटन करता है और यह निर्णय लेता है कि उत्पादन के कौन से तरीके अपनाए। उत्पादन साधनों का कितना भाग पूंजी पदार्थों और कितना भाग उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर आवंटित किया जाए।

2. पूंजी संचय (Capital Accumulation)—मुद्रा के माध्यम से ही पूंजी सचय संभव है। पूंजी संचय के लिए आवश्यक तरलता और गतिशीलता, मुद्रा ही प्रदान करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निवेश निधियों के स्रोत लगभग वही होते हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत।

Scanned with CamScanner

पण्यावर्त कर (turnover tax), सार्वजनिक उद्यमों के योजनाबद्ध लाभ, परिशोधन कोटे (amortisation quotas), और जिन्स में अथवा नीची वसूली कीमतों (procurement prices) के रूप में कृषि-उत्पादन पर कराधान—ये सब मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं और पूंजी संचय में सहायक होते हैं।

3. विदेश व्यापार (Foreign trade)—समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं वस्तु-सौदों के आधार पर द्विपक्षीय संबंध स्थापित करके विदेशी व्यापार नहीं करतीं बल्कि क्योंकि वे विश्व बैंक तथा IMF की सदस्य हैं, इसलिए वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-संबंधों में मुद्रा के रूप में ही भुगतान करती हैं।

4. मुद्रा कर का चक्रीय प्रवाह (Circular Flow of Money)—समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चक्रीय प्रवाह भी होता है। उत्पादन करने वाली इकाइयों को निवेश के लिए निधियां राज्य-बजट से या तो अनुदान के रूप में प्राप्त होती हैं या फिर राज्य-बैंक से कर्जे के रूप मिलती हैं ताकि वे आवश्यक लागतों को खरीद सकें और मजदूरों को भुगतान कर सकें। मजदूर अपनी मजदूरी उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय करते हैं। उत्पादन करने वाली इकाइयों को विक्रय से आमदनी होती है। ये निधियां दोबारा राज्य-बजट और राज्य-बैंक से उत्पादन इकाइयों में प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा, वस्तुओं तथा सेवाओं के चक्रीय प्रवाह में सहायक होती है।

निष्कर्ष (Conclusion)—निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शायद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में समाजवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत राज्य के नियमन और नियंत्रण के कारण मुद्रा कम महत्त्व रखती है। फिर भी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा कीमतों, मजदूरी, आय और लाभ के निर्धारण में सहायक होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा उसके संसाधनों का समुचित बंटवारा करने में, पूंजी संचय में और अर्थव्यवस्था के भीतर तथा बाहर संसाधनों का प्रवाह निर्धारित करने में मार्ग-दर्शन करती है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा का कार्य
(ROLE OF MONEY IN A MIXED ECONOMY)

मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि मुक्त बाजार की क्रियाएं और आयोजन साथ-साथ कार्य करते हैं। परन्तु सभी आर्थिक क्रियाएं, यहां तक कि बाजार क्रियाएं भी, सरकार के निर्देशन और नियंत्रण के अनुसार कार्य करती हैं। इस दृष्टिकोण से मिश्रित अर्थव्यवस्था में मुद्रा के निम्न कार्य होते हैं—

1. वित्त प्रबंधन (Financing)—नियोजित अर्थव्यवस्था में मुद्रा बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। वित्तीय और भौतिक आयोजन को अपनाने के लिए मुद्रा का पर्याप्त मात्रा में पाया जाना बहुत आवश्यक है। मुद्रा के बिना योजना का वित्तप्रबंधन करना सम्भव नहीं होता। इसके लिए घाटे का वित्तप्रबंधन, करों की वसूली, ऋण व्यवस्था, विदेशी सहायता आदि मुद्रा द्वारा ही होते हैं।

2. विकास योजनाओं का निर्माण (Construction of Development Projects)—मुद्रा द्वारा सरकार विकास योजनाओं का निर्माण करती है और विकास के लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान करती है। इसके लिए सरकार स्वयं निवेश करती है, उत्पादन के लिए साधनों का सीधे प्रबन्ध करती है तथा आर्थिक एवं सामाजिक उपरिसुविधाएं प्रदान करती है।

3. वस्तुओं और सेवाओं का क्रय-विक्रय (Sale—Purcalse of Goods and Services)—नियोजित ढंग से वस्तुओं और सेवाओं का आन्तरिक तथा विदेशी बाजारों में क्रय एवं विक्रय मुद्रा द्वारा ही सम्भव होता है।

Scanned with CamScanner

4. सार्वजनिक क्षेत्र का प्रसार और लेखांकन (Expansion and Accounting of Public Sector)—मुद्रा द्वारा सरकार योजनाबद्ध तरीके से देश के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर पिछड़े हुए क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यम स्थापित करती है और उसका प्रसार करती है। मुद्रा से ही इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की लागतों तथा कीमतों की हिसाब लगाती है।

5. निजी क्षेत्र को सहायता (Help to Private Sector)—प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में सरकार मुद्रा द्वारा निजी उद्यमों को सुविधाएं प्रदान करती है। योजना की आवश्यकताओं के अनुसार, निवेश तथा उत्पादन की प्रेरणा देने के लिए सामाजिक और आर्थिक उपरिसुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त, निजी क्षेत्र को सस्ते ऋण, आर्थिक सहायता तथा कर-छूट दी जाती है।

6. विनिमय-अर्थव्यवस्था का विकास (Development of Exchange Economy)—जो अल्पविकसित देश विकास के प्रथम चरण में होते हैं उनमें अधिकतर वस्तु-विनिमय प्रणाली पाई जाती है। यह विकास में बाधा उत्पन्न करती है। इसलिए सरकार गैर-मौद्रिक क्षेत्र में बचत बैंक खोलकर, निर्माण कार्य प्रारम्भ करके और उद्योग स्थापित करके मुद्रा का चलन बढ़ाती है जिससे विनिमय अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ऐसा मुद्रा के लेन-देन द्वारा सम्भव होता है।

7. अन्य कार्य (Other functions)—एक ओर तो मुद्रा आर्थिक विकास में सहायता करती है, दूसरी ओर यह अनेक बाधाएं भी उत्पन्न करती है। इसका अधिक प्रसार स्फीति, विदेशी विनिमय तथा भुगतान-शेष की समस्याएं लाता है। इनको नियंत्रित करने के लिए सरकार मुद्रा के अत्यधिक प्रसार को रोकती है।

Scanned with CamScanner